

## NIA न्यायालय ने धर्मांतरण मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में लखनऊ में एक वशिष्ठ [राष्ट्रीय अनवेषण अभिकरण \(NIA\) न्यायालय](#) ने अवैध [धर्मांतरण](#) मामले में इस्लामिक वद्वान और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

### मुख्य बंदि

- आरोप और दोषसदिधि:
  - दोषियों पर [उत्तर प्रदेश वधि विरुद्ध धर्म संपरविरतन प्रतषिध अधनियिम, 2021](#) की धारा 121A (राज्य के वरुद्ध कुछ अपराध करने की साज़शि रचना), धारा 123 (युद्ध छेडने की योजना को सुवधिजनक बनाने के मन्तव्य से छपाना), धारा 153A (धर्म के आधार पर वभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढावा देना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
- गरिफ्तारी और आरोप:
  - इस्लामिक स्कॉलर को 2021 में [उत्तर प्रदेश के आतंकवाद नरिधी दसुते](#) ने मेरठ से अवैध धर्म परविरतन के लयि एक [राष्ट्रव्यापी सडिकेट](#) चलाने के आरोप में गरिफ्तार कयि था।
  - उन पर शत्रुता को बढावा देने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को क्षतपिहुँचाने तथा धर्मांतरण को बढावा देने हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठनों से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था।

### राष्ट्रीय अनवेषण अभिकरण (NIA)

- NIA भारत की [केंद्रीय आतंकवाद नरिधी कानून परवर्तन एजेंसी](#) है, जसि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावति करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने का अधिकार है। इसमें शामिल हैं:
  - वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
  - परमाणु एवं नाभिकीय सुवधिओं के वरुद्ध।
  - हथियारों, नशीले पदार्थों और [जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ](#)।
  - [संयुक्त राष्ट्र](#), उसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों तथा प्रस्तावों को लागू करने के लयि बनाए गए वैधानिक कानूनों के अंतर्गत अपराध।
- इसका गठन [राष्ट्रीय अनवेषण अभिकरण \(NIA\) अधनियिम, 2008](#) के तहत कयि गया था।
- एजेंसी को [गृह मंत्रालय](#) की लखिति घोषणा के तहत राज्यों से वशिष्ठ अनुमति के बनि राज्यों में आतंकवाद से संबंधति अपराधों की जाँच करने का अधिकार है।
- मुख्यालय: नई दलिली

### उत्तर प्रदेश वधि विरुद्ध धर्म संपरविरतन प्रतषिध अधनियिम, 2021

- इस कानून में धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण के संबंध में कड़े प्रावधान हैं।
- इसमें **20 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास** का प्रावधान है, अगर यह पाया गया कि धर्म परविरतन धमकी, शादी का वादा या साजशि के तहत कयि गया है
  - वधियक के तहत इसे सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- यह वधियक **कसि भी व्यक्त को धर्म परविरतन** से संबंधति मामलों में [प्रथम सूचना रपिरट \(FIR\)](#) दर्ज करने की अनुमति देता है, न कि केवल माता-पति, पीड़ति या भाई-बहन को।
- इन मामलों की सुनवाई, सत्र न्यायालय से नीचे के कसि न्यायालय में नहीं होगी। वधियक में इस अपराध को [गैर-जमानती भी बनाया गया है](#)।
  - जो कोई भी व्यक्त विविह के उद्देश्य से अपनी इच्छा से धर्म परविरतन करना चाहता है, उसे संबंधति ज़िला मजसि्ट्रेट को दो महीने पहले आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

